Dainik Bhaskar (Indore), 03rd May 2026, Page – 08

सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशंस इन ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस पर सेमिनार

विकास के साथ प्रकृति को भी संभालना है, इसलिए ग्रीन बिल्डिंग जरूरी : सीएम

विशेष संवाददाता | भोपाल

मप्र में अब ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट केवल बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों या आलीशान बंगलों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार अब ऐसी निर्माण तकनीकों पर जोर दे रही है, जिससे आम नागरिक भी कम बजट में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष घर बना सके। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को आयोजित 'सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशंस इन ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस' विषय पर दो दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार में यह विजन सामने आया।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान समय की बड़ी चुनौती यह है कि हम कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और सिमटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच खड़े हैं। ऐसे में पर्यावरण अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। उन्होंने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है, लेकिन अधोसंरचना विकास में राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए हम ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईआईटी इंदौर और लोक निर्माण विभाग के बीच निर्माण तकनीक पर केंद्रित एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही, पीडब्ल्यूडी और गृहा (GRIHA) संस्था के बीच भी एक समझौता हुआ।

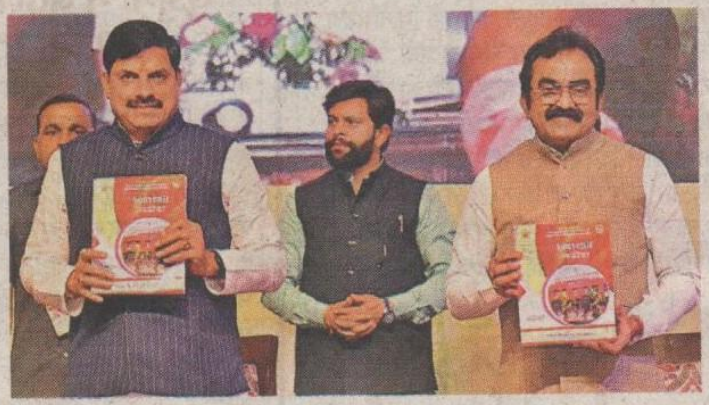

कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव व मंत्री राकेश सिंह ने पुस्तक का विमोचन किया

हर वर्ग के लिए बने किफायती प्लान

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सेमिनार में विशेषज्ञों से आह्वान किया कि आर्किटेक्चर समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टिकाऊ निर्माण के लिए प्राचीन भारतीय तकनीकों को अपनाया जा रहा है और अब राज्य के सभी सरकारी भवन ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर ही बनाए जा रहे हैं। सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश में बन रहे हाईवे और फ्लाइओवर्स को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक से लैस किया जा रहा है, ताकि जल संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

▪ नई तकनीक और आत्मनिर्भरता पर जोर

आईबीसी के संस्थापक अध्यक्ष ओपी गोयल ने कहा कि इंजीनियरिंग सेक्टर में नए सॉफ्टवेयर और थ्रीडी प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। सेमिनार में वास्तु शास्त्री संदीप चौबे सहित करीब 30 तकनीकी विशेषज्ञों ने ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन और प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस जैसे विषयों पर विचार रखे। विशेषज्ञों का साझा लक्ष्य नई तकनीकों के माध्यम से भारत को अधोसंरचना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए 'विकसित भारत' का निर्माण करना है।